भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 591

06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अर्बन हीट आइलैंड (यूएचआई) प्रभाव

591. श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश के प्रमुख शहरों में बढ़ते अर्बन हीट आइलैंड (यूएचआई) प्रभाव की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हरित छतों और शहरी वानिकी को बढ़ावा देने सहित यूएचआई प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशेष उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने परामर्शिका के रूप में राज्यों को "भारत शीतलन कार्य योजना 2019" पर मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल)-2016 का परिशिष्ट जारी किया है। (https://www.mohua.gov.in/upload/whatsnew/61b9785b508c3mbbl2016.pdf)

शहरी हरित दिशानिर्देश, 2014 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में जारी किया गया है (https://www.mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/G%20G%202014(2).pdf)।

अध्याय 5 - शहरी नियोजन दृष्टिकोण के माध्यम से आवास**न** और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई)

दिशा-निर्देश खुले स्थानों/हरित स्थानों और मनोरंजन के उद्देश्य के लिए अधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए कॉम्पैक्ट और ग्रीन सिटी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जिससे अर्बन हीट आइलैंड कम बनेंगे। (mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI Guidelines Vol I(2).pdf)

इसके अलावा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत 1,522.09 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,442 पार्क परियोजनाओं को विकसित किया गया है, जिससे 5,077 एकड़ हरित क्षेत्र विकसित हुआ है। अब तक, अमृत 2.0 के तहत 1,049.63 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,676 पार्क परियोजनाओं और 6,214.15 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,032 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिया गया है।

*****